भारत सरकार
खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 3115
18 दिसंबर, 2025 को उत्तर देने के लिए

उचित भंडारण के अभाव में फलों और सब्जियों की बर्बादी

3115. डॉ. आनन्द कुमार गोंड:

क्या **खाद्य प्रसंस्करण उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या यह सच है कि भारत फलों और सब्जियों का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है और इनमें से बड़ी मात्रा में फल और सब्जियां खराब प्रसंस्करण और उचित भंडारण के अभाव के कारण बर्बाद हो जाती हैं, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ख) क्या सरकार इस तथ्य से अवगत है कि देश में होटल प्रबंधन, आहार विशेषज्ञ आदि क्षेत्रों में पूर्णकालिक पाठ्यक्रम उपलब्ध हैं, लेकिन खाद्य प्रसंस्करण के क्षेत्र में समर्पित पाठ्यक्रमों या कौशल प्रशिक्षण की कमी है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ग) क्या सरकार का फलों और सब्जियों के बेहतर प्रबंधन और मूल्यवर्धन को बढ़ावा देने के लिए खाद्य प्रसंस्करण से संबंधित ऐसे समर्पित पाठ्यक्रम या कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू करने का प्रस्ताव है; और
(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो क्या सरकार का निकट भविष्य में ऐसा करने का प्रस्ताव है; यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग राज्य मंत्री
(श्री रवनीत सिंह)

(क): जी हाँ, यह तथ्य है कि भारत फलों और सब्ज़ियों का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है। इसके अतिरिक्त, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद –केंद्रीय फसलोत्तर अभियांत्रिकी और प्रौद्योगिकी संस्थान (आईसीएआर-सिफेट), 2015 और नाबार्ड कंसल्टेंसी सर्विस प्राइवेट लिमिटेड (नैबकोंस), 2022 के अध्ययन के अनुसार, भारत में फलों और सब्ज़ियों की फसल कटाई और फसलोत्तर नुकसान का अनुमानित प्रतिशत इस तरह है:

फसलें/वस्तुएं	**अनुमानित प्रतिशत हानि**	
	आईसीएआर-सिफेट अध्ययन (2015) के अनुसार	**नैबकोंस अध्ययन (2022) के अनुसार**
फल	6.70-15.88	6.02-15.05
सब्ज़ियाँ	4.58-12.44	4.87-11.61

फलों और सब्जियों की फसल सहित कृषि उपज के फसलोत्तर नुकसान को कम करने के उद्देश्य से, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय (एमओएफपीआई) केंद्रीय क्षेत्र की अम्ब्रेला योजना "प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना (पीएमकेएसवाई)" और केंद्र प्रायोजित "प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम उन्नयन (पीएमएफएमई) योजना "

की विभिन्न घटक योजनाओं के माध्यम से प्रसंस्करण/परिरक्षण क्षमता के निर्माण हेतु खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों की स्थापना में सहायता प्रदान करता है। पीएमकेएसवाई की शुरूआत से पूरे देश में कुल 1619 परियोजनाओं को स्वीकृत किया गया है, जिनमें से 31 अक्टूबर, 2025 तक 1181 परियोजनाएं पूरी हो चुकी हैं, जिससे 269.61 लाख मीट्रिक टन प्रति वर्ष की प्रसंस्करण और परिरक्षण क्षमता का निर्माण हुआ है । इसके अतिरिक्त, पीएमएफएम योजना के तहत, 31 अक्टूबर , 2025 तक देश में सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम शुरू करने/अपग्रेड करने के लिए 162744 इकाइयों को ऋण मंज़ूर किए गए हैं।

(ख) से (घ): जी हां । सरकार ने खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में कौशल अंतर को कम करने के लिए कई पहल की हैं। कौशल प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए, खाद्य उद्योग क्षमता और कौशल पहल (एफआईसीएसआई), खाद्य प्रसंस्करण के लिए क्षेत्र कौशल परिषद, जिसे कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय (एमएसडीई) द्वारा स्थापित किया गया था, के पास राष्ट्रीय व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण परिषद (एनसीवीईटी) द्वारा अनुमोदित 60 से अधिक जॉब रोल हैं। इन जॉब रोल को उद्योग की आवश्यकताओं के आधार पर विशेषज्ञों द्वारा बनाए योग्यता पैक के अनुसार अनुमोदित किया जाता है । उद्योग की वर्तमान आवश्यकताओं को दर्शाने के लिए सभी योग्यता पैक हर 36 महीने के बाद अपडेट किए जाते हैं । अनुमोदित जॉब रोल में पौधे आधारित प्रोटीन, फर्टिफाइड खाद्य और सूक्ष्म क्रेडेंशियल्स जैसे उभरते क्षेत्र शामिल हैं जो एफएसएसएआई द्वारा अनिवार्य आवश्यकताओं और खाद्य उत्पादों की सुरक्षा और अखंडता सुनिश्चित करने के लिए डिजाइन किए गए ढांचे को कवर किया गया है। इसके अतिरिक्त खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय इसकी स्कीमों और संस्थानों के माध्यम से सेक्टर संबंधित अल्पकालिक प्रशिक्षण प्रदान करना सुनिश्चित करता है।

इसके अतिरिक्त, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय की प्रधान मंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम उन्नयन (पीएमएफएमई) स्कीम में एक क्षमता निर्माण प्रशिक्षण घटक है, जिसके तहत राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारें क्षमता निर्माण प्रशिक्षण प्रदान करती हैं। इसमें जिला स्तरीय समिति (डीएलसी) द्वारा ऋण से जुड़े अनुदान लेने के लिए सिफ़ारिश किए गए सभी आवेदक यानी व्यक्तियों और समूहों (एसएचजी/एफपीओ/सहकारी समितियों) के लिए खाद्य प्रसंस्करण ईडीपी (उद्यमिता विकास कार्यक्रम) 24 घंटे/3 दिन का अल्पावधि प्रशिक्षण, और सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण में कार्यरत स्कीम के तहत प्रारम्भिक पूंजी के एसएचजी लाभार्थियों को को 8 घंटे/1 दिन के प्रशिक्षण परिकल्पित है। वर्ष 2020-21 से 2024-25 तक पूरे भारत में 1,09,312 लाभार्थियों को प्रशिक्षण प्रदान किया गया है।

उपरोक्त के अतिरिक्त, इस मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में तंजावुर (तमिलनाडु) और कुंडली (हरियाणा) में स्थित दो राष्ट्रीय महत्व के संस्थान (आईएनआई) यानी राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी उद्यमिता एवं प्रबंधन संस्थान (निफ्टेम) भी स्नातक और स्नातकोत्तर डिग्री पाठ्यक्रम चला रहे हैं तथा खाद्य प्रौद्योगिकी और प्रबंधन में डिग्री दे रहे हैं। इसके अलावा, निफ्टेम ने अपने अल्पावधि कौशल /क्षमता निर्माण/उद्यमिता विकास कार्यक्रम के माध्यम से , वर्ष 2018-19 से 2024-25 की अवधि के दौरान क्रमशः 32255 और 1516 लोगों को प्रशिक्षण प्रदान किया है।

इसके अलावा कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के तहत खाद्य उद्योग क्षमता और कौशल पहल (एफआईसीएसआई) और खाद्य प्रसंस्करण के लिए क्षेत्र कौशल परिषद, ने शैक्षिक और तकनीकी संस्थानों के साथ भागीदारी में विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किए हैं। एफआईसीएसआई ने वर्ष 2015-16 से खाद्य प्रसंस्करण जॉब रोल में 2.72 लाख से अधिक उम्मीदवारों को प्रशिक्षण और प्रमाणीकरण प्रदान किया है, जिसमें विद्यालयों, आईटीआई, पॉलिटेक्निक, खाद्य प्रौद्योगिकी संस्थानों, खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों और राज्य कौशल मिशन के सहयोग से चलाई जा रही प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (पीएमकेवाई) के अंतर्गत 2.60 लाख उम्मीदवार शामिल हैं ।

*****